ने लम्बे स्टेपल तथा छोटे स्टेपल रूई के उत्पादन के लिए कोई निश्चित राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं ।

(ख) चालू रूई वर्ष 1988-89 के दौरान भारतीय कपास निगम का निम्नलिखित रूप में विभिन्न राज्यों में 240 खरीद केन्द्र चलाने का प्रस्ताव है :

राज्य	केन्द्रों की संख्या
पंजाब . . .	20
हरियाणा . . .	15
राजस्थान . . .	25
मध्य प्रदेश . . .	40
गुजरात . . .	65
आन्ध्र प्रदेश . . .	45
कर्नाटक . . .	20
तमिलनाडु . .	10
योग :	240

इस समय कपास की बाजार कीमतें न्यूनतम समर्थन स्तरों से अधिक हैं । जब कभी भी बाजार कीमतें न्यूनतम समर्थन कीमतों के स्तर पर पहुंचती हैं, निगम इन केन्द्रों का संचालन करना प्रारंभ कर देगा ।

(ग) एक और उपजकर्ता निकाय तो निर्यात कोटा की रिलीज के लिए अभिवेदन दे रहे हैं किंतु दूसरी ओर मिलों के संगठन रूई निर्यात के विरुद्ध प्रतिवेदन दे रहे हैं । अब तक कपास के निर्यात के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

मुद्रास्फीति के संबंध में विश्व बैंक की चेतावनी

895. **श्री राम नरेश यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने गत वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि को देखते हुए भारत सरकार को चेतावनी दी थी ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं ; और

(ग) देश में मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि को देखते हुए विश्व बैंक द्वारा क्या आशंकाएं व्यक्त की गयी थीं और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ।

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) :

(क) से (ग) वर्ष 1988 के लिए विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कृषि मूल्यों पर सूखे का प्रभाव पड़ने के कारण, भारत में 1980 के दशक के प्रारंभ से पहली बार मुद्रास्फीति लगभग 10 प्रतिशत तक पहुंच गई ।

रिपोर्ट में सूखे के कुप्रभावों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा समय पर की गई कार्यवाही और इस प्रकार की आपात स्थितियों का सामना करने के लिए सुस्थापित संस्थापन तंत्र की मौजूदगी के लिए भारत की सराहना की गई है । केन्द्रीय सरकार ने, अपने खाद्यान्न भंडार से खाद्यान्न जारी करके और खाद्यतेलों, दालों और चारे का आयात करके मूल खाद्यान्नों की उपलब्धता को बनाए रखा है और कीमतों में वृद्धि को नियंत्रण में रखा है ।

Decline in the export of engineering goods

396. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) what is the comparative percentage of decline in the export of engineering goods as against the target in 1988 (till date) as compared to the same period during 1987;

(b) what are the names of the countries where the export of engineering goods have shown a decline stating the reasons therefor; and

(c) what measures are contemplated by Government to step up the export of engineering goods?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. R. DAS MUNSHI): (a) There is no decline, Sir. The exports of engineering goods for the period April—September, 1988 are Rs. 635 crores and for the period April—September, 1987 were Rs. 486.75 crores. This represents a growth of 30.45 per cent for the same period in the last year.

(b) Commodity-wise break-up of exports to individual countries during 1987-88 and 1988-89 are not available.

(c) A number of measures have been taken by Government to boost export of engineering goods. These *inter-alia* include liberalisation of licensing procedures and technology import, Cash Compensatory Support, access to raw materials and consumables at international competitive prices, reduction in the interest rates of pre & post shipment credit, interest rebate on new term loans to units which export more than 25 per cent of their production, assistance from export marketing fund for marketing activities abroad, introduction of new blanket exchange permit scheme to facilitate export promotion activities, grant of replenishment licences, duty drawback etc.

Central Laws Enacted for Punjab since President's Rule

897. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what are the details of the Central laws enacted for the State of Punjab since the promulgation of President's Rule in the State in May, 1987;

(b) whether the Committee constituted under the Punjab Legislature (Delegation of Powers) Act, 1987 was consulted about any of these Acts;

(c) if not, whether it was not known much before the actual enactment that these Acts would have to enforced by the President in the absence of the State Legislative Assembly; and

(d) if so, what were the reasons for not taking the necessary steps in each of these cases well in advance?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Since the Promulgation of President's Rule in Punjab the following acts concerning the State of Punjab have been enacted by the President under the Punjab Legislature (Delegation of Powers) Act, 1987:

(i) The Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Temporary Supersession) Amendment Act, 1987. (President's Act No. 1 of 1987);

(ii) The Punjab Municipal (Amendment) Act, 1987. (President's Act No. 2 of 1987);

(iii) The Punjab Agricultural produce Markets (Amendment) Act, 1987. (President's Act No. 3 of 1987);

(iv) The Punjab Agricultural produce Markets (Second Amendment) Act, 1987. (President's Act No. 4 of 1987);

(v) The Punjab Contingency Fund (Amendment) Act, 1988 (President's Act No. 5 of 1988); and

(vi) The Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Temporary Supersession) Amendment Act, 1988 (President's Act No. 8 of 1988).